तालीम पर ताला

स्कूली शिक्षा पर आपात रिपोर्ट

(6 सितंबर, 2021)

गरीब परिवारों के करीब 1,400 बच्चों के बीच हाल में किए गए एक सर्वेक्षण से पिछले डेढ़ साल के दौरान लंबे अरसे तक स्कूल बंद होने के अनर्थकारी नतीजे सामने आए हैं. सर्वेक्षण में शामिल ग्रामीण इलाकों के सिर्फ 8 फीसद बच्चे नियमित रूप से ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, 37 फीसद बिल्कुल पढ़ ही नहीं रहे हैं, और करीब आधे कुछेक शब्दों से ज्यादा नहीं पढ़ सकते. ज्यादातर अभिभावक चाहते हैं कि स्कूल जल्द से जल्द खुलें.

स्कूल सर्वे 2021: प्रमुख नतीजे*

	शहरी	ग्रामीण
सर्वे में शामिल उन बच्चों का अनुपात (%) जो:		
नियमित रूप से ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं	24	8
आजकल बिल्कुल पढ़ नहीं रहे हैं	19	37
पिछले 30 दिनों में अपने शिक्षक/शिक्षकों से मिले नहीं	51	58
पिछले 3 महीने के दौरान कोई परीक्षा नहीं दी	52	71
कुछ शब्दों से ज्यादा पढ़ नहीं सकते	42	48
सर्वे में शामिल उन अभिभावकों का अनुपात (%) जो मानते हैं कि:		
उनके बच्चे को पर्याप्त ऑनलाइन शिक्षा मिलती है	23	8
लॉकआउट के दौरान उनके बच्चे की पढ़ने की क्षमता घट गई है	76	75
स्कूल दोबारा खुलना चाहिए	90	97

स्कूल सर्वे, पहला राउंड, अगस्त 2021 (1,362 घर, कक्षा 1-8 के 1,362 बच्चे)

तालीम पर ताला

स्कूली शिक्षा पर आपात रिपोर्ट*

गरीब परिवारों के करीब 1,400 बच्चों के बीच हाल में किए गए एक सर्वेक्षण से पिछले डेढ़ साल के दौरान लंबे अरसे तक स्कूल बंद होने के अनर्थकारी नतीजे सामने आए हैं. सर्वेक्षण में शामिल ग्रामीण इलाकों के सिर्फ 8 फीसद बच्चे नियमित रूप से ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, 37 फीसद बिल्कुल पढ़ ही नहीं रहे हैं, और करीब आधे कुछेक शब्दों से ज्यादा नहीं पढ़ सकते. ज्यादातर अभिभावक चाहते हैं कि स्कूल जल्द से जल्द खुलें.

गरीब परिवारों के करीब 1,400 बच्चों के बीच हाल में किए गए एक सर्वेक्षण से पिछले डेढ़ साल के दौरान लंबे अरसे तक स्कूल बंद होने के अनर्थकारी नतीजे सामने आए हैं. सर्वेक्षण में शामिल ग्रामीण इलाकों के सिर्फ 8 फीसद बच्चे नियमित रूप से ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, 37 फीसद बिल्कुल पढ़ ही नहीं रहे हैं, और करीब आधे कुछेक शब्दों से ज्यादा नहीं पढ़ सकते. ज्यादातर अभिभावक चाहते हैं कि स्कूल जल्द से जल्द खुलें.

देश में प्राइमरी और अपर-प्राइमरी स्कूल (प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल) पूरे 17 महीने यानी 500 से भी ज्यादा दिनों से बंद हैं ! इस दौरान बहुत कम सुविधासंपन्न बच्चे अपने घरों के सुखद और सुरक्षित माहौल में ऑनलाइन पढ़ाई कर पाए. लेकिन स्कूल की तालेबंदी की वजह से बाकी बच्चों के लिए खास कोई चारा

---

* स्कूल सर्वे देशभर के करीब 100 वॉलंटियर्स का संयुक्त प्रयास था. यह रिपोर्ट कोऑर्डिनेशन टीम (निराली बाखला, ज्यां द्रेज़, विपुल पैकरा, रीतिक खेड़ा) ने तैयार की है, जिसमें अंकिता अग्रवाल, सृजना बेज, अश्लेष बिरादर, कृष्णा प्रिया चोरागुडी, हिंडोली दत्ता, आशीष गुप्ता, पल्लवी कुमारी, जेसिका पुदुस्सेरी, आरती तावडे, कणिका शर्मा, तेजस्विनी तभाने और गरिमा टोपनो जैसे कई वॉलंटियर्स ने दिल खोलकर मदद की है. दूसरे संगठनों (अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी, भारत ज्ञान विज्ञान समिति और एमवी फाउंडेशन की कंपेनियन सर्वे पर काम चल रहा है. अँग्रेज़ी से सटीक और त्वरित अनुवाद के लिए मोहम्मद वक़ास को शुक्रिया.

नहीं बचा. कुछ ने ऑनलाइन या ऑफलाइन पढ़ाई जारी रखने के लिए संघर्ष किया. कई दूसरे बच्चों ने हार मान लिया और काम-धंधा न होने की घड़ी में गांव या बस्ती में आवारागर्दी करते रहे. वे न केवल पढ़ने के अधिकार बल्कि स्कूल जाने से मिलने वाले दूसरे फायदों, जैसे सुरक्षित माहौल, बढ़िया पोषण और स्वस्थ सामाजिक जीवन से भी वंचित हो गए. इस लंबी 'तालेबंदी' के अनर्थकारी नतीजों को समझने का वक्त आ गया है.

इस आपात रिपोर्ट में स्कूल चिल्ड्रेंस ऑनलाइन ऐंड ऑफलाइन लर्निंग (स्कूल) सर्वे के नतीजों को पेश किया गया है. यह स्कूल सर्वे अगस्त 2021 में 15 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में किया गयाः असम, बिहार, चंडीगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल (जिन्हें अब से ''स्कूल प्रदेश'' लिखा जाएगा). इस सर्वे में अपेक्षाकृत वंचित गांवों और बस्तियों पर ध्यान दिया गया, जहां बच्चे अमूमन सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं. सर्वे में शामिल 1,362 परिवारों में से प्रत्येक में हमने प्राइमरी या अपर प्राइमरी कक्षा में पढ़ने वाले एक बच्चे से बात की.

इस सर्वे से उभरने वाली तस्वीर, खासकर ग्रामीण इलाकों में पूरी तरह निराशाजनक है. आवरण पृष्ठ पर सार में दिए गए इसके नतीजे अपनी तर्जुमानी खुद करते हैं. ग्रामीण इलाकों में इस सर्वे के वक्त केवल 28 फीसद बच्चे नियमित रूप से पढ़ाई कर रहे थे, और 37 फीसद बिल्कुल नहीं पढ़ रहे थे (अधिक ब्यौरे के लिए देखें टेबल 1). पढ़ने की आसान-सी परीक्षा के नतीजे खासकर चौंकाने वाले हैंः सर्वे में शामिल करीब आधे बच्चे कुछ ही शब्द पढ़ पाए. ज्यादातर अभिभावकों का मानना है कि तालाबंदी के दौरान उनके बच्चे की पढ़ने-लिखने की क्षमता कम हो गई. वे स्कूल खुलने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. दरअसल, उनमें से कई के लिए स्कूली शिक्षा इकलौती उम्मीद है जिससे उनके बच्चों की जिंदगी उनकी खुद की जिंदगी से बेहतर होगी.

टेबल 1: क्या बच्चे पढ़ रहे हैं?*

	शहरी	ग्रामीण
ऐसे सैम्पल बच्चों का अनुपात (%) जो:		
नीयमित रूप से पढ़ रहे हैं	47	28
कभी कभी पढ़ रहे हैं	34	35
बिलकुल नहीं पढ़ रहे हैं	19	37

* सर्वे के समय की स्थिति (1-8 कक्षाओं में नामांकित बच्चे)। पिछले तीन महीनों में भी ऐसी सी ही स्थिति थी।

स्कूल सर्वे

इस स्कूल सर्वे को उन वॉलंटियर्स (मुख्यतः यूनिवर्सिटी के स्टुडेंट्स) ने अंजाम दिया, जिन्होंने अगस्त 2021 के शुरू में जारी की गई एक अपील के प्रति दिलचस्पी जताई. इसके दिशानिर्देशों में आग्रह किया गया था कि वे इस सर्वे को ग्रामीण और शहरी बस्तियों में करें जहां ''सुविधाओं से वंचित परिवार रहते हैं—ऐसे परिवार जो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजते हैं.'' उन्हें चुनिंदा इलाकों में घर-घर जाने को कहा गया था (समान अंतराल पर उन घरों को ''छोड़ना'' था जहां पूरा कवरेज के लिए पर्याप्त वक्त नहीं था, और उन घरों को भी छोड़ देना था जिनमें कोई बच्चा प्राइमरी या अपर-प्राइमरी क्लास में नहीं पढ़ता हो). सार यह है कि इस सर्वे में जानबूझकर सुविधाओं से वंचित परिवारों पर ध्यान दिया गया, और इसके नतीजों को इसी की रोशनी में पढ़ा जाना चाहिए.

करीब 1,400 परिवारों (मूल परिवार के रूप में परिभाषित) से बातचीत की गई. सर्वे में शामिल करीब 60 फीसद परिवार ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, और करीब 60 फीसद दलित या आदिवासी समुदायों (टेबलओं में अनुसूचित जाति/जनजाति) के हैं. करीब आधे सैंपल चार राज्यों के हैंः दिल्ली, झारखंड, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश. सर्वे में शामिल ये बच्चे (जिन्हें ''स्कूल चिल्ड्रेन'' लिखा जाएगा) जेंडर और ग्रेड के मामले में कमोबेश बराबर से शामिल हैं. स्कूल सैंपल के बारे में अधिक ब्यौरे के लिए देखें परिशिष्ट 1.

इस आपात रिपोर्ट में हम सभी स्कूल प्रदेशों के आंकड़ों को एक साथ, और ग्रामीण तथा शहरी इलाकों के आंकड़ों को अलग-अलग पेश कर रहे हैं. विस्तृत रिपोर्ट तैयार हो रही है.

ऑनलाइन शिक्षा का अफसाना

स्कूल सर्वे ने साफ कर दिया है कि ऑनलाइन शिक्षा की पहुंच सीमित हैः ''नियमित रूप से'' ऑनलाइन पढ़ाई करने वाले स्कूल चिल्ड्रेन का अनुपात शहरी इलाकों में महज 24 फीसद और ग्रामीण इलाकों में 8 फीसद था. इसकी एक वजह यह है कि कई सैंपल परिवारों (ग्रामीण इलाकों में करीब आधे) के पास स्मार्टफोन नहीं है. लेकिन यह महज पहली बाधा हैः जिन परिवारों के पास स्मार्टफोन है, उनमें भी नियमित रूप से ऑनलाइन पढ़ाई करने वाले बच्चों का अनुपात शहरी इलाकों में महज 31 फीसद और ग्रामीण इलाकों में 15 फीसद है. स्मार्टफोन का इस्तेमाल अक्सर कामकाजी वयस्क लोग करते हैं, और वे स्कूली बच्चों, खासकर छोटे सहोदरों को शायद ही कभी मिलते हैं (सभी स्कूल चिल्ड्रेन में से केवल 9 फीसद

बच्चों के पास अपना स्मार्टफोन था). इसके अलावा, खराब कनेक्टिविटी और 'डेटा' के लिए पैसे की कमी (टेबल 2) जैसी ऑनलाइन एक्सेस की दूसरी दिक्कतें हैं. जिन अभिभावकों ने यह माना कि उनके बच्चे की 'पर्याप्त ऑनलाइन एक्सेस' थी, उनका अनुपात शहरी इलाकों में महज 23 फीसद और ग्रामीण इलाकों में 8 फीसद था. खासकर ग्रामीण इलाकों में एक और बड़ी बाधा यह है कि स्कूल ऑनलाइन सामग्री नहीं भेज रहा है, या अगर भेज भी रहा है तो अभिभावकों को उसकी जानकारी नहीं है. वैसे भी खासकर छोटे बच्चों को ऑनलाइन अध्ययन की समझ नहीं है, या उन्हें ध्यानकेंद्रित करने में परेशानी होती है.

टेबल 2: औनलाईन पढ़ाई में कई मुश्किलें

	शहरी	**ग्रामीण**
स्कूल सर्वे के ऐसे बच्चों का अनुपात (%):		
जिनके परिवार के पास स्मार्टफ़ोन है	77	51
जो नियमित रूप से औनलाईन पढ़ाई कर रहे हैं	24	8
जिन परिवारों में स्मार्टफ़ोन हैं, उनमें बच्चों के नीयमित रूप से औनलाईन न पढ़ने के कारण * (%)		
बच्चे के पास अपना खुद का स्मार्टफ़ोन नहीं है	30	36
ख़राब कनेक्टिविटी ("नेटवर्क")	9	9
"डेटा" के लिए पैसे नहीं है	9	6
बच्चे को औनलाईन पढ़ाई समझ नहीं आती	12	10
स्कूल कोई औनलाईन सामग्री नहीं भेजता	14	43
अन्य	15	10

* माता-पिता द्वारा बताया गाया (अधिकतम दो कारण दे सकते हैं).

टेबल 3 उन बच्चों पर केंद्रित है जो सर्वे के वक्त नियमित या कभी-कभार ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे थे. उन्हें संक्षेप में 'ऑनलाइन चिल्ड्रेन' कहा गया है. ऑनलाइन चिल्ड्रेन के सीखने का अनुभव खास उत्साहित नहीं करता. उनमें से ज्यादातर को कनेक्टिविटी की दिक्कतें हैं, और लगभग आधे को ऑनलाइन वीडियो (या अगर कोई क्लास चल रही हो) को समझने में परेशानी होती है. यही नहीं, बहुत कम अभिभावक

अपने बच्चे की ऑनलाइन अध्ययन सामग्री से संतुष्ट हैं. जैसा कि आगे बताया गया है कि ऑनलाइन चिल्ड्रेन के दो-तिहाई अभिभावक मानते हैं कि तालाबंदी के दौरान उनके बच्चे की पढ़ने-लिखने की क्षमता कम हो गई है.

टेबल 3: "औनलाईन बच्चों" में औनलाईन पढ़ाई का अनुभव *

	शहरी	**ग्रामीण**
ऐसे औनलाईन बच्चों का अनुपात (%):		
जिनका अपना स्मार्टफ़ोन है	11	12
जो वीडियो के अलावा लाईव क्लासें भी देखते हैं	27	12
जिनको कनेक्टिविटी की समस्या होती है (अक्सर या कभी कबार)	57	65
जिन्हें औनलाईन क्लासें/वीडियो समझने में दिक्कत होती है	46	43
औनलाईन बच्चों के ऐसे माता-पिता का अनुपात (%):		
जिन्हें लगता है कि उनके बच्चे के पास पर्याप्त औनलाईन सुविधा है	44	25
जो औनलाईन पढ़ाई की सामग्री से संतुष्ट हैं	29	20
जिन्हें लगता है कि लौकडाउन के दौरान उनके बच्चे के पढ़ने और लिखने की क्षमता *कम* हुई है	65	70

* औनलाईन बच्चे वे हैं जो सर्वे के समय औनलाईन (कभी कभी या नियमित रूप से) पढ़ाई कर रहे थे – स्कूल सर्वे के कुल 25.5% बच्चे, शहरी बच्चों का प्रतिनिधित्व ज़्यादा है।

ऑफलाइन अध्ययन बहुत कम

'ऑफलाइन चिल्ड्रेन' (सर्वे के वक्त जो ऑनलाइन पढ़ाई नहीं कर रहे थे) के बीच इसके सबूत बहुत कम हैं कि वे नियमित अध्ययन कर रहे हैं. उनमें से ज्यादातर या तो बिल्कुल पढ़ ही नहीं रहे हैं, या फिर अपने घर पर कभी-कभार खुद पढ़ लेते हैं. ग्रामीण इलाकों में करीब आधे बच्चे सर्वे के दौरान बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर रहे थे. असम, बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में तालाबंदी के दौरान ऑफलाइन चिल्ड्रेन की पढ़ाई जारी रखने में मदद के लिए वस्तुतः कुछ नहीं किया गया. कर्नाटक, महाराष्ट्र, पंजाब और राजस्थान जैसे राज्यों में कुछ प्रयास किए गए हैं; मिसाल के तौर पर, ऑफलाइन चिल्ड्रेन को

होमवर्क के लिए ‘वर्कशीट्स’ दिए गए, या शिक्षकों को अभिभावकों के घर समय-समय पर जाकर उनसे मशविरा करने का निर्देश दिया गया. लेकिन अभिभावकों और बच्चों की गवाहियों के मद्देनजर ही नहीं बल्कि इस तथ्य के भी मद्देनजर कि तालाबंदी के दौरान बच्चों की लिखने-पढ़ने की क्षमताएं बुरी तरह घट गईं, इनमें से ज्यादातर कोशिशें संतोषजनक नहीं हैं (देखें नीचे). खासकर सबसे कम उम्र के बच्चे, मसलन, ग्रेड 1 और 2 वाले किसी भी तरह की मदद पाने से वंचित रह गए.

ऑफलाइन अध्ययन के साधन

ऑफलाइन अध्ययन के मुख्य साधन (मुख्यतः शहरी इलाकों में) प्राइवेट ट्यूशन थे, और ज्यादातर मामलों में परिवार के दूसरे सदस्यों की मदद या बगैर मदद से घर पर ही पढ़ाई चल रही थी. लेकिन घर पर पढ़ाई के ज्यादातर मामलों में बच्चा ‘नियमित रूप से’ पढ़ने के बजाए ‘कभी-कभार’ पढ़ रहा था. केवल प्राइवेट ट्यूशन में ही, जो अपेक्षाकृत बहुत कम सुविधासंपन्न बच्चों तक सीमित है, नियमित पढ़ाई में सामान्य बात है (टेबल 4).

टेबल 4: स्कूल सर्वे के बच्चों का अनुपात (%) जो अभी विभिन्न तरीकों से पढ़ाई कर रहे हैं

	शहरी		**ग्रामीण**	
	नीयमित	कभी कभी	नीयमित	कभी कभी
औनलाईन क्लासें या वीडियो	25	16	8	8
टीवी पर शिक्षात्मक कार्यक्रमों द्वारा	3	5	0.1	1
निजी ट्यूशन	24	6	14	4
परिवार की सहायता से घर पर पढ़ाई	15	29	12	25
बिना किसी की सहायता से घर पर पढ़ाई	19	30	15	31
दोस्तों से साथ पढ़ाई, एक दूसरे के घर में	2	13	3	11
ऊपर दिए गए किसी भी तरीके से				
कम से कम कभी कभी	81		64	
नीयमित रूप से *	53		29	

* सर्वे प्रश्नावली का एक अलग भाग प्रयोग करने के कारण टेबल 1 से कुछ भिन्नता है।

टीवी आधारित शिक्षा अपने आप में फ्लॉप मालूम होती है. दूरदर्शन पर स्कूली बच्चों के लिए नियमित शैक्षिक प्रसारण होता है, लेकिन हमारे सैंपल में सिर्फ 1 फीसद शहरी और 8 फीसद ग्रामीण बच्चों ने टीवी प्रोग्रामों को अध्ययन के नियमित या कभी-कभार के साधन के रूप में स्वीकार किया.

स्कूल की पहुंच

टेबल 5 में ऑफलाइन चिल्ड्रेन के लिए स्थानीय स्कूल (अमूमन कोई सरकारी स्कूल) की ओर से शैक्षिक समर्थन के दूसरे संकेत पेश किए गए हैं. यह समर्थन बहुत छिट-पुट है, और कुछ राज्यों के ग्रामीण इलाकों में वस्तुतः बिल्कुल नहीं है. समर्थन का मुख्य रूप 'होमवर्क' है, जो सिद्धांततः समझदारी भरा उपाय है, लेकिन व्यावहारिक रूप में हमेशा कारगर नहीं होता. मिसाल के तौर पर, होमवर्क बच्चे की समझ से परे होता है, और कई बच्चों को उनके होमवर्क के बारे में कोई जानकारी नहीं दी जाती. किसी भी तरह से होमवर्क क्लास में पढ़ाई का कमज़ोर विकल्प ही है, खासकर उन बच्चों के लिए जिन्हें घर पर किसी तरह की मदद नहीं मिलती. इसी तरह, शिक्षक की ओर से कभी-कभार फोन से बहुत मदद नहीं मिलती, खासकर जब मामला आधार कार्ड या राशन कार्ड से जुड़ा हो. शहरी इलाकों में 27 फीसद ऑफलाइन चिल्ड्रेन ने बताया कि पिछले तीन महीने में कोई परीक्षा हुई थी, लेकिन इन परीक्षाओं की प्रकृति हमेशा स्पष्ट नहीं होती थी. कभी-कभी इसका मुख्य उद्देश्य बच्चे की मदद करने से ज्यादा रिपोर्टिंग जरूरतों को पूरा करने में शिक्षक की मदद करना मालूम देता है.

संपर्क से परे शिक्षक

इस सर्वे के 30 दिन पहले तक ज्यादातर बच्चों (शहरी इलाकों में 51 फीसद और ग्रामीण इलाकों में 58 फीसद) की अपने शिक्षक से भेंट नहीं हुई थी. कुछ ही अभिभावकों ने बताया कि पिछले तीन महीने के दौरान कोई शिक्षक घर पर नहीं आया या पढ़ाई में उनके बच्चे की कोई मदद नहीं की. गाहे-बगाहे उनमें से कुछेक (या ज्यादातर उनके अभिभावकों) को व्हाट्सऐप के जरिए यूट्यूब लिंक फॉरवर्ड करने जैसे सांकेतिक ऑनलाइन इंटरैक्शन को छोड़कर ज्यादातर शिक्षक अपने छात्रों से बेखबर लगते हैं.

वहीं दूसरी ओर, कुछ शिक्षकों ने ऑफलाइन चिल्ड्रेन की मदद के लिए विशेष प्रयास किए. दरअसल, इस सर्वे में पता चला कि ध्यान रखने वाले शिक्षकों ने कई तरह की शानदार पहल की. कुछ ने खुले आसमान के नीचे छोटे समूह में, या किसी के घर पर या यहां तक कि अपने घर पर ही क्लास लगाए. दूसरों ने उन बच्चों के फोन को रिचार्ज कराया जिनके पास पैसे नहीं थे, या फिर ऑनलाइन अध्ययन के

लिए अपना फोन दे दिया. कई अन्य शिक्षकों ने कुछ छात्रों को फोन के जरिए या यहां तक उनके पास जाकर पढ़ाई में उनकी मदद की. यकीनन ये सब काबिले तारीफ पहल हैं, लेकिन ये बंद स्कूलों और खाली क्लासरूम्स की भरपाई नहीं कर सकते.

टेबल 5: "औफ़लाईन बच्चों" के लिए शैक्षात्मक सहयोग*

	शहरी	ग्रामीण
ऐसे "औफ़लाईन बच्चों" का अनुपात (%) जिन्हें पिछले तीन महीनों में स्थानीय स्कूल से शैक्षात्मक सहयोग का लाभ पाया:		
स्कूल ने घर पर या कही और एक परीक्षा की व्यवस्था की	27	16
शिक्षक ने बच्चे को कुछ गृहकार्य दिया	39	25
बच्चे के बारे में पता लगाने या उसे सहाल देने के लिए शिक्षक घर आए	5	12
शिक्षक ने फ़ोन पर बच्चे के बारे में पता लगाया या सहाल दी	36	13
शिक्षक ने बच्चे को घर पर सहायता की	3	2
कोई अन्य शैक्षात्मक सहयोग **	6	5

* औफ़लाईन बच्चे वे हैं जो सर्वे के समय औनलाईन पढ़ाई नहीं कर रहे थे।

** उदाहरण: स्कूल में क्लासों का आयोजन हुआ (उदाहरण के लिए पंजाब); मोहल्ला क्लासें; शिक्षक फ़ोन पर सहायता करते हैं; औनलाईन पढ़ाई के लिए शिक्षक अपना फ़ोन उधार देते हैं; शिक्षक ने कहानियों की किताब दी; शिक्षक ने बच्चों का फ़ोन रीचार्ज किया; स्कूल ने टैबलेट दिया; शिक्षक मुफ़्त ट्यूशन देते हैं; शिक्षक बच्चे को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं; माता-पिता और शिक्षक के बीच बैठक.

प्राइवेट स्कूलों से पलायन

मार्च 2020 में जब तालाबंदी शुरू हुई तब करीब 20 फीसद स्कूल चिल्ड्रेन ने किसी प्राइवेट स्कूल में दाखिला ले रखा था. लॉकआउट के दौरान कई प्राइवेट स्कूलों ने ऑनलाइन शिक्षा अपनाकर उबरने का प्रयास किया और पुरानी फीस लेना जारी रखा. गरीब अभिभावक कमाई कम होने या अपने बच्चों के लिए ऑनलाइन शिक्षा के कारगर न होने की वजह से अक्सर फीस और दूसरे खर्च (स्मार्टफोन और रिचार्ज समेत) देने में आनाकानी करते. शायद मुख्यतः इसी वजह से कई बच्चों ने सरकारी स्कूलों में दाखिला ले लिया—हमारे सैंपल के करीब 26 फीसद बच्चे, जो शुरू में प्राइवेट स्कूलों में दाखिल थे.

हमारी मुलाकात ऐसे अभिभावकों से भी हुई जो तब तक अपने बच्चों का दाखिला किसी सरकारी स्कूल में कराने के लिए जद्दोजहद रहे थे क्योंकि प्राइवेट स्कूल उन्हें 'ट्रांसफर सर्टिफिकेट' जारी करने से पहले बकाया फीस वसूलने की जिद पर अड़े थे.

बंद हुआ मिडडे मील

स्कूल बंद होने के साथ ही सारे सैंपल प्रदेशों में मिडडे मील बंद कर दिया गया. सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे के अभिभावकों में से करीब 80 फीसद ने बताया कि पिछले तीन महीने के दौरान उनके बच्चे के मिडडे मील के बदले कुछ अनाज (मुख्यतः चावल या आटा) मिला—देखें टेबल 6. लेकिन बहुत कम लोगों को कोई नकद मिला, और काफी लोगों को उस दौरान कुछ भी नहीं मिला. इसके अलावा, जिन लोगों को कुछ खाद्यान्न मिला, उनमें से कई ने शिकायत की या संकेत दिया कि अभिभावक जितना पाने (प्राइमरी स्तर पर प्रति बच्चा प्रति दिन 100 ग्राम) के हकदार थे, उससे कम मिला. कुल मिलाकर, मिडडे मील के विकल्पों का वितरण काफी छिट-पुट और बेतरतीब मालूम देता है.

टेबल 6: सरकारी स्कूलों में मध्याह्न भोजन के एवज़ में विकल्प

	शहरी	**ग्रामीण**
सरकारी स्कूलों में नामांकित ऐसे बच्चों का अनुपात (%) जिन्हें पिछले 3 महीनों में मध्याह्न भोजन के एवज में खाना या पैसा मिला		
खाना और पैसा	11	15
केवल खाना	69	63
केवल पैसा	0	8
कुछ नहीं	20	14

नोट: अगर बच्चे के माता-पिता को खाना (या पैसा) मिला, तो भी माना गया है कि खाना (या पैसा) मिला है। अधिकांश जगह खाने का मतलब है अनाज (उदाहरण के लिए चावल या गेहूं)। कुछ मामलों में जहां तीन महीनों से अधिक अंतराल में वितरण होता है, वहाँ भी जवाब "कुछ नहीं" है।

पढ़ने का परीक्षण

इस सर्वे में बुनियादी पढ़ाई का परीक्षण शामिल था: बच्चों को बड़े आकार में छपे एक आसान वाक्य को पढ़ने के लिए कहा गया और वह वाक्य था—'जब से कोरोना महामारी चल रही है तब से स्कूल बंद है'.

इसके नतीजे चौंकाने वाले थे (देखें टेबल 7): फिलहाल ग्रेड 3-5 में भर्ती आधे बच्चे कुछेक शब्दों से ज्यादा नहीं पढ़ पाए. ग्रामीण इलाकों में 42 फीसद बच्चे एक भी शब्द नहीं पढ़ सके.

टेबल 7: पढ़ने की परीक्षा: पढ़ने की क्षमता के अनुसार बच्चों का अनुपात (%)*

	शहरी		ग्रामीण	
	3-5 की कक्षाएँ	6-8 की कक्षाएँ	3-5 की कक्षाएँ	6-8 की कक्षाएँ
अच्छे से पढ़ पाए	31	58	26	57
मुश्किल से पढ़ पाए	22	23	19	19
कुछ शब्द ही पढ़ पाए	13	8	13	8
कुछ अक्षर ही पढ़ पाए	35	12	42	16

* इसमें ऐसे 44 बच्चों को शामिल नहीं किया है जिन्होंने पढ़ने से शर्माया। कौलम का कुल 100% (या 101%, "राउंडिंग के कारण")।

ग्रेड 2 के बच्चों को तो टेबल 7 में शामिल तक नहीं किया गया क्योंकि उनमें से ज्यादातर (शहरी इलाकों में 65 फीसद और ग्रामीण इलाकों में 77 फीसद) बमुश्किल कुछ अक्षर पढ़ पाए. ध्यान रहे कि इनमें से ज्यादातर बच्चे कभी स्कूल नहीं जा सके (पिछले साल तालाबंदी के दौरान ग्रेड 1 में उनका दाखिला कराया गया था). जल्दी ही वे ग्रेड 3 में चले जाएंगे.

यहां तक कि अपर-प्राइमरी स्तर (ग्रेड 6-8) पर भी आसानी से पढ़ लेने वाले बच्चों का शहरी और ग्रामीण इलाकों में अनुपात आधे से महज थोड़ा ज्यादा थाा. उम्र और ग्रेड के हिसाब से पढ़ने के परीक्षण का ब्यौरा परिशिष्ट 2 में दिया गया है—उस पर एक नजर जरूर डालें.

पढ़ने की घटती क्षमताएं

पढ़ने के परीक्षण के निराशाजनक नतीजे कुछ हद तक तालाबंदी से पहले स्कूल में खराब पढ़ाई-लिखाई के स्तर को दर्शाते हैं. अलबत्ता, यह भी है कि कई बच्चों ने जो भी सीखा था, उसमें से वे ज्यादातर भूल गए. ज्यादातर अभिभावकों का मानना था कि तालाबंदी के दौरान उनके बच्चे की पढ़ने-लिखने की क्षमता कम हो गई है. यहां तक कि 'ऑनलाइन चिल्ड्रेन' वाले शहरी अभिभावकों के बीच भी ऐसा मानने वालों का अनुपात 65 फीसद था, जो बहुत बड़ी संख्या है. समग्र सैंपल में से केवल 4 फीसद अभिभावकों का

माननाथा कि तालाबंदी के दौरान उनके बच्चे की पढ़ने-लिखने की क्षमता सुधरी है—जबकि यही सामान्य बात होनी चाहिए थी.

टेबल 8: बच्चों की पढ़ने और लिखने की क्षमताओं में गिरावट

	शहरी	**ग्रामीण**
ऐसे माता-पिताओं का अनुपात (%) जिन्हें लगता है कि जबसे लौकडाउन शुरू हुआ है, तब से उनके बच्चों के पढ़ने और लिखने की क्षमता कम हुई है:		
औनलाईन बच्चे	65	70
औफ़लाईन बच्चे	82	76
1-5 कक्षाएँ *	78	79
6-8 कक्षाएँ *	72	70

* वर्तमान नामांकन।

नीचे सरकी साक्षरता दर

हालत की गंभीरता को समझने के लिए हम स्कूल चिल्ड्रेन की साक्षरता दर की तुलना 2011 की जनगणना में उसी आयु वर्ग में औसत साक्षरता दर से कर सकते हैं. जनगणना के मुताबिक, उस समय बिहार के अलावा सभी स्कूल प्रदेशों में 10-14 वर्ष के आयु वर्ग में औसत साक्षरता दर 88 फीसद से 99 फीसद के बीच थी (बिहार में 83 फीसद थी); अखिल भारतीय औसत 91 फीसद था. कोई भी उम्मीद करेगा कि दस साल बाद उस आयु वर्ग में साक्षरता दर 90 फीसद से ज्यादा हो गई होगी. लेकिन 10-14 आयु वर्ग के स्कूल चिल्ड्रेन के बीच शहरी इलाकों में साक्षरता दर घटकर 74 फीसद, ग्रामीण इलाकों में 66 फीसद और ग्रामीण दलितों तथा आदिवासियों के बीच 61 फीसद हो गई है (टेबल 9).

यह गैर-बराबरी और भी ज्यादा चौंकाने वाली लगती है क्योंकि साक्षरता की सरकारी जनगणना वाली परिभाषा (किसी भी भाषा में समझकर पढ़ने-लिखने की क्षमता) टेबल 9 में स्कूल सर्वे के आंकड़ों के लिए इस्तेमाल की गई परिभाषा के मुकाबले ज्यादा पाबंदियां लगाने वाली लगती है. स्कूल चिल्ड्रेन के बीच इतनी जबरदस्त गैर-बराबरी की व्याख्या केवल उनकी वंचित पृष्ठभूमि के नज़रिए से नही हो सकती.

टेबल 9: साक्षरता का स्तर, 10-14 वर्ष उम्र

	स्कूल सर्वे, 2021			भारत की जनगणना, 2011 (ग्रामीण + शहरी)*
	शहरी	ग्रामीण	ग्रामीण दलित/ आदीवासी	
लोग	74	66	61	91
पुरुष	74	66	61	92
महिला	74	67	60	90

* जिन 15 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में स्कूल सर्वे हुआ, उनकी जनसंख्या के अनुसार औसतन।

नोट: स्कूल सर्वे के आँकड़ों में उन बच्चों को साक्षर माना है जो परीक्षा के वाक्य को "आसानी से" या "मुश्किल से" पढ़ पाए। भारत की जनगणना 2011 उनको साक्षर मानती है जो "किसी भी भाषा में पढ़ने व लिखने में सक्षम हैं" – यह परिभाषा स्कूल सर्वे में साक्षरता की परिभाषा से *ज़्यादा कठिन* लगती है।

इसे दूसरी तरह से देखा जाए तो स्कूल सैंपल में ग्रामीण अनुसूचित जाति/जनजाति परिवारों के 10-14 आयु वर्ग के बीच 'निरक्षरता दर' 39 फीसद है, जो दस साल पहले स्कूल प्रदेशों 10-14 आयु वर्ग के सभी बच्चों के बीच निरक्षरता दर 9 फीसद से चार गुना ज्यादा है. ये लंबे अरसे से गैर-बराबरी और असंतुलित तालाबंदी का मिला-जुला असर है.

दलित और आदिवासीः सबसे अधिक प्रभावित

जैसा कि साक्षरता के आंकड़ों से जाहिर है, दलित और आदिवासी परिवारों की हालत स्कूल सैंपल के औसत से ज्यादा खराब है. ग्रामीण इलाकों (शहरी इलाकों पर भी इसी तरह का पैटर्न लागू होता है) के लिए इसका ब्यौरा टेबल 10 में दिया गया है. यहां तक कि वंचित परिवारों के बीच दलित और आदिवासी परिवारों के आंकड़े दूसरों के मुकाबले ज्यादा खराब हैं, चाहे हम ऑनलाइन शिक्षा को देखें, या नियमित अध्ययन, या पढ़ने की क्षमता. मिसाल के तौर पर, महज 4 फीसद ग्रामीण अनुसूचित जाति/जनजाति के बच्चे नियमित ऑनलाइन अध्ययन कर रहे हैं, जबकि दूसरे ग्रामीण बच्चों में यह अनुपात 15 फीसद है. पढ़ने के परीक्षण में बमुश्किल आधे बच्चे कुछेक अक्षरों से ज्यादा पढ़ सके. ग्रामीण अनुसूचित जाति/जनजाति के 98 फीसद अभिभावक चाहते थे कि जितना जल्द मुमकिन हो स्कूल खोला जाए.

टेबल 10: और भी तालाबंद: दलित व आदीवासी *

	दलित/ आदीवासी	अन्य
ऐसे बच्चों का अनुपात (%) जिनके घर में स्मार्टफ़ोन नहीं है	55	38
ऐसे बच्चों का अनुपात (%) जो:		
बिलकुल पढ़ाई नहीं कर रहे हैं	43	25
नियमित रूप से पढ़ाई कर रहे हैं	22	40
नीयमित रूप से औनलाईन पढ़ाई कर रहे हैं	4	15
ऐसे औनलाईन बच्चों का अनुपात (%) जो न केवल वीडियो, पर औनलाईन क्लासें भी देखतें हैं	5	29
ऐसे औनलाईन बच्चों के माता-पिता का अनुपात (%) जो औनलाईन अध्ययन सामग्री से संतुष्ट हैं	13	26
ऐसे बच्चों का अनुपात (%) जो केवल कुछ अक्षर ही पढ़ पाए	45	24
साक्षरता का दर, उम्र 10-14 वर्ष (%)	61	77
ऐसे माता-पिता का अनुपात (%) जिनको लगता है कि लौकडाउन के दौरान उनके बच्चे की लिखने-पढ़ने की क्षमता कम हुई है	83	66

* केवल ग्रामीण क्षेत्र; शहरी क्षेत्रों में भी ऐसा ही अंतर है।

इस सर्वे ने स्कूल व्यवस्था में दलितों और आदिवासियों के साथ भेदभाव के कुछ आंखें खोल देने वाले मामले उभारे. झारखंड में लातेहार जिले के कुटमु गांव में ज्यादातर दलित और आदिवासी परिवार हैं, लेकिन शिक्षिका गांव के चंद अगड़ी जाति के परिवारों में से एक की सदस्य हैं. इन परिवारों के कुछ सदस्यों ने सर्वे करने वाली टीम से सरेआम सवाल कियाः ''अगर ये (अनुसूचित जाति/जनजाति) के बच्चे पढ़-लिख जाएंगे तो हमारे खेतों में कौन काम करेगा ?'' शिक्षिका करीब के कस्बे में रहती हैं, जब मर्जी आती है तब स्कूल आती हैं, और क्लासरूम में आराम फरमाती हैं. हमने कुटमु में जिन 20 दलित और आदिवासी बच्चों से बातचीत की, उनमें कोई भी आसानी से पढ़ने में सक्षम नहीं था. उनके अभिभावकों ने उस शिक्षिका के गैर-जिम्मेदाराना रवैये की जमकर शिकायत की, लेकिन इस बाबत वे कुछ करने में लाचार थे.

प्रगति के बिना प्रोन्नति

पढ़ने-लिखने की क्षमता में बड़े पैमाने पर गिरावट के बावजूद बच्चों को ऊंची क्लासों में प्रमोट किया जाता रहा है—तालाबंदी के पहले के स्तर से दो ग्रेड ऊपर. वे ऊंची क्लास में तो पहुंच जा रहे हैं, जहाँ पाठ्यपुस्तकों का स्तर उनकी पढ़ाई के मौजूदा स्तर से ऊंचा है. मिसाल के तौर पर कुछ राज्यों में जो बच्चे कभी स्कूल नहीं गए, फिलहाल वे ग्रेड 2 में हैं, और अब उनसे उम्मीद की जाती है कि वे अंग्रेजी की पाठ्यपुस्तक पढ़ें !

स्कूल खुलने के साथ ही बच्चों को पता चलने वाला है कि वे अपने ग्रेड के पाठ्यक्रम से 'तीन दर्जे पीछे' हैं. इस तिहरी दरार में (1) तालाबंदी से पहले की दरार, (2) तालाबंदी के दौरान साक्षरता और संबंधित योग्यताओं में गिरावट, और (3) उस दौरान पाठ्यक्रम में आगे की प्रगति शामिल है. मिसाल के तौर पर, तालाबंदी से पहले किसी बच्ची का ग्रेड 3 में दाखिला तो हो गया लेकिन दरअसल वह अपनी सुविधाहीन स्थिति की वजह से ग्रेड 2 के आगे के पाठ्यक्रम में महारत हासिल न कर सकी, और अब इस मामले में वह खुद को ग्रेड 1 के करीब पाती है. आज वह ग्रेड 5 में पहुंच गई है, और चंद महीनों में अपर-प्राइमरी क्लास में पहुंचने वाली है ! इस व्यापक बेमेलपन को दूर करने के लिए पाठ्यक्रम और पढ़ाने के तरीके में लंबे अरसे तक बड़े बदलाव की जरूरत है—इसमें महीनों के बजाए बरसों लग सकते हैं.

दिशाहीन हुए बच्चे

बाल मज़दूरी के मामलों में इजाफा तालाबंदी का संभावित नतीजा हो सकता है. स्कूल सर्वे के नतीजों के मद्देनजर 10 साल से कम उम्र के बच्चों में बाल मजदूरी अब भी असामान्य बात है, लेकिन 10-14 आयु वर्ग में काफी हद तक सामान्य है. मिसाल के तौर पर उस आयु वर्ग की ज्यादातर लड़कियां कोई न कोई घरेलू काम कर रही हैं. ग्रामीण इलाकों में उसी आयु वर्ग की एक-चौथाई लड़कियों ने पिछले तीन महीने के दौरान परिवार के खेतों में बेगारी की थी, और 8 फीसद ने मज़दूरी की थी. समान आयु वर्ग में लड़कों के साथ भी ऐसा ही है, लेकिन घरेलू काम करने वाले लड़कों का आंकड़ा कम है.

एक ओर जहां कुछ बच्चे मज़दूरी करने लगे हैं, वहीं दूसरे बच्चे बेकारी, कसरत की कमी, फोन की लत, पारिवारिक तनाव और तालाबंदी के दूसरे दुष्प्रभावों से जूझ रहे हैं. हालांकि स्कूल सर्वे का मुख्य फोकस यह नहीं था लेकिन कई अभिभावकों ने इस तरह की चिंताएं जाहिर की. मिसाल के तौर पर, कुछ अभिभावकों ने शिकायत की कि उनके बच्चे अनुशासनहीन, आक्रामक और यहां तक कि हिंसक हो गए हैं. खासकर शहरी इलाकों के अभिभावकों को ज्यादातर वक्त बच्चों का घर के आसपास होना बोझ

लगने लगा, या वे घर के बाहर बच्चे की गतिविधियों और उसकी सोहबत को लेकर फिक्रमंद थे. घर से बाहर काम करने वाली मांओं के लिए स्कूल बंद होना किसी आफत से कम नहीं है.

स्कूल खोलने की जोरदार मांग

हमने जिन अभिभावकों से बातचीत की उनमें से ज्यादातर चाहते हैं कि स्कूल जल्दी से जल्दी खुलें. शहरी इलाकों में बहुत कम (लगभग 10 फीसद) अभिभावकों को इस बारे में कुछ झिझक थी, और यहां तक कि कुछ अभिभावकों ने स्कूल खोलने का विरोध किया. लेकिन ग्रामीण इलाकों में 97 फीसद अभिभावकों ने स्कूल खोलने का समर्थन किया. जब हमने पूछा कि क्या वे स्कूल दोबारा खुलवाना चाहते हैं, उनमें से ज्यादातर को लगा कि इस का जवाब खुद जाहिर है. एक मां ने इस सवाल पर ताज्जुब जताते हुए कहा, ''यह पूछने वाली बात है?''

सर पर खड़ी आफत

स्कूल आवश्यक सेवा हैं. सही ही कहा गया है कि उन्हें सबसे आखिर में बंद करना चाहिए और सबसे पहले खोलना चाहिए. लेकिन अपने देश में इसके उलट हो रहा हैः 2020 के शुरू में कोविड-19 संकट आते ही सारे स्कूल झट से बंद कर दिए गए और उनमें से ज्यादातर अभी तक बंद हैं. स्कूल खुलने के बाद सारा ध्यान छोटे बच्चों के बजाए बड़ी क्लासों पर है, जबकि छोटे बच्चों को शिक्षकों की मदद सबसे ज्यादा दरकार है. ऑनलाइन शिक्षा के छद्म आवरण से 17 महीने तक स्कूल तालाबंदी से हुई तबाही को ढकने की कोशिश की गई. इस घोर नाइंसाफी पर इतने लंबे वक्त तक वस्तुतः कोई सवाल न खड़ा करना भारत के एक्सक्लूसिव लोकतंत्र पर बेहद गहरा दाग है.

स्कूल सर्वे से विस्तृत तालाबंदी—दुनिया में सबसे लंबी में से एक—से हुए बड़े पैमाने पर नुक्सान का अंदाजा लगता है. हमने देखा कि खुद अभिभावक इस नुक्सान से वाकिफ हैं. उनमें से कई ने अपनी मायूसी जताते हुए कहा, ''बच्चा का लाइफ तो खतम ही हो रहा है''.

इस नुक्सान की भरपाई के लिए बरसों तक धैर्य से काम करना होगा. स्कूल खोलना महज पहला कदम है, जिस पर अब भी बहस जारी है. हकीकत तो यह है कि कई राज्यों में इस पहले कदम की तैयारी (जैसे स्कूल की इमारतों की मरम्मत, कोविड सुरक्षा के दिशानिर्देश जारी करना, शिक्षकों का प्रशिक्षण, दाखिले की मुहिम) लगभग नदारद है. उसके बाद स्कूल व्यवस्था को न केवल बच्चों को तर्कसंगत पाठ्यक्रम से तालमेल बनाने बल्कि उनकी मानसिक, सामाजिक और पोषण संबंधी भलाई के लिए लंबे संक्रमण काल

से गुजरने की जरूरत है. अभी के हालात के मद्देनजर लगता है कि स्कूल खुलने के बाद व्यवस्था ''पुराने ढर्रे'' पर लौट आएगी—यह आफत का नुस्खा है.

अनुबंध 1: स्कूल परिवार व बच्चे

	शहरी	ग्रामीण
सैम्पल परिवारों की संख्या	520	842
परिवारों का विवरण		
विभिन्न श्रेणियों का अनुपात (%)		
दलित (SC)	44	47
आदीवासी (ST)	5	20
ओबीसी (OBC)	16	20
अन्य	24	9
अस्पष्ट	12	5
निम्न आजीविका कितने प्रतिशत (%) उत्तरदाताओं की एक "मुख्य आजीविका"[a] है		
खेती	2	36
गैर-खेतिहर स्व-रोज़गार	20	15
अनौपचारिक मज़दूरी	48	60
अनुबंध पर काम	12	7
नियमित रोज़गार	12	5
घर का काम	16	14
अन्य	11	3
प्रतिशत (%) जिनके पास स्मार्टफ़ोन है	77	51
बच्चों का विवरण		
जेंडर का अनुपात (%)		
पुरुष	54	50
महिला	46	50
ट्रांसजेंडर	0	0
कक्षाओं का अनुपात[b] (%)		
पहली और दूसरी कक्षाएँ	19	18
तीसरी और चौथी कक्षाएँ	24	27
पाँचवी और छठी कक्षाएँ	33	31
सातवीं और आठवीं कक्षाएँ	24	24
कितने प्रतिशत (%) निम्न में नामांकित हैं :		
सरकारी स्कूल	74	84
निजी स्कूल	21	11
अन्य	5	5
राज्य-वार सैम्पल संख्या		
झारखंड	32	182

दिल्ली	185	6
महाराष्ट्र	3	160
उत्तर प्रदेश	5	155
ओडीशा	0	93
हरयाणा	39	49
कर्नाटक	70	3
पंजाब	35	24
असम	33	23
बिहार	6	46
अन्य राज्य/केंद्र शासित प्रदेश[c]	112	101

[a] हर उत्तरदाता के लिए अधिकतम दो मुख्य आजीविकाएँ

[b] पहली और दूसरी कक्षाओं का कम प्रतिनिधित्व लौकडाउन के दौरान नामांकन में समस्याओं के कारण हो सकता है।

[c] "अन्य राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश" वे हैं जिनमें 50 से कम परिवारों का सैम्पल है: चंडीगढ़ (45), राजस्थान (40), पश्चिम बंगाल (38), तमिल नाडु (35), मध्य प्रदेश (34), गुजरात (21).

अनुबंध 2: पढ़ने की परीक्षा

बच्चों का अनुपात, पढ़ने की क्षमता के अनुसार *

	अच्छे से पढ़ पाए	मुश्किल से पढ़ पाए	कुछ शब्द ही पढ़ पाए	कुछ अक्षर ही पढ़ पाए
शहरी				
दूसरी कक्षा	9	9	17	65
तीसरी कक्षा	23	9	16	52
चौथी कक्षा	26	26	13	36
पाँचवी कक्षा	41	28	10	22
छठी कक्षा	49	21	11	20
सातवीं कक्षा	69	19	5	7
आठवीं कक्षा	58	31	6	6
ग्रामीण				
दूसरी कक्षा	7	13	3	77
तीसरी कक्षा	11	14	14	61
चौथी कक्षा	31	26	7	36
पाँचवी कक्षा	33	19	17	31
छठी कक्षा	48	20	9	22
सातवीं कक्षा	59	23	6	12
आठवीं कक्षा	66	13	7	13

* इसमें ऐसे 44 बच्चों को शामिल नहीं किया है जो पढ़ने से शर्माए। अंकों का कुल 100% है, पंक्ति-वार ("राउंडिंग" के कारण कुछ जगह कुल 99% या 101% है).